RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 207
दि. 28.11.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.
Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

संविधान दिवस:'नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य निभाएं', पर पीएम ने लिखा देशवासियों के नाम बेहद खास लेटर

(जीएनएस)।

संविधान दिवस के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक भावनात्मक और प्रेरक संदेश भेजा है। अपने इस पत्र में उन्होंने न सिर्फ संविधान की ऐतिहासिक यात्रा को याद किया, बल्कि हर नागरिक को यह भी बताया कि भारत के भविष्य को मजबूत बनाने में कर्तव्य निभाना कितना महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत उसी मजबूत नींव पर खड़ा है, जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निमार्ताओं ने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से तैयार किया था।

पीएम ने अपने अनुभव और देश की लोकतांत्रिक ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान ने साधारण से साधारण व्यक्ति को भी बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अधिकार दिया है। यह संदेश ऐसे

समय आया है जब देश 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है और नागरिकों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

1949 से आज तक संविधान ने दी दिशा

पीएम मोदी ने कहा कि 1949 में जब भारत का संविधान अपनाया गया, तभी से यह दस्तावेज देश को साफ दिशा और भरोसा देता आया है। उन्होंने याद दिलाया कि 2015 में उनकी सरकार ने 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरूआत की थी।

साधारण परिवार से देश की सेवा का मौका

प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान की ताकत से ही साधारण परिवार से आने वाले लोग भी देश की बागडोर संभाल सकते हैं। उन्होंने 2014 का वह पल याद किया जब पहली बार संसद में प्रवेश करते समय उन्होंने संसद की सीढ़ियों को नमन किया था। 2019 में दोबारा जीत के समय उन्होंने संविधान को माथे से लगाकर सम्मान दिया था।

पीएम मोदी ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद, डॉ भीमराव आंबेडकर और महिलाओं सहित सभी सदस्यों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि इन सभी की मेहनत से भारत को इतना मजबूत संविधान मिला।

पीएम ने 2010 की 'संविधान गौरव यात्रा' का जिक्र किया, जिसमें गुजरात में संविधान की प्रति को हाथी पर रखकर यात्रा निकाली गई थी। उन्होंने बताया कि संविधान के 75 साल पूरे होने पर देशभर में कई कार्यक्रम और संसद का विशेष सत्र आयोजित हुआ था।

पीएम मोदी ने कहा कि इस बार का संविधान दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल सरदार वल्लभभाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इन दोनों महान नेताओं ने देश के लिए महत्वपूर्ण काम किए।

नागरिको के कर्तव्यों पर जोर

प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 51अ का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें बताए गए कर्तव्यों को हर नागरिक को गंभीरता से निभाना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी के विचार को याद दिलाया कि जब कर्तव्य पूरे होते हैं, तभी अधिकार मिलते हैं।

2049 तक की यात्रा में जिम्मेदारी और बढ़ेगी

पीएम मोदी ने कहा कि इस सदी के 25 साल बीत चुके हैं और आने वाले दो दशको में भारत आजादी के 100 साल और संविधान के 100 साल पूरे करेगा। उन्होंने कहा कि आज लिए गए फैसले आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेंगे। इसलिए विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्तव्य को सबसे ऊपर रखना होगा।

पहली बार वोट करने वाले युवाओं के लिए खास कार्यक्रम का सुझाव

प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट डालना सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य है। उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूल और कॉलेज में 18 साल के होने वाले युवाओं के लिए छोटे समारोह आयोजित किए जाएं, ताकि उन्हें महसूस हो कि वे देश निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अंत में पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प लें और विकसित, मजबूत भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।

कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं हो सकता : योगी

मुख्यमंत्री ने लोकभवन में संविधान की उद्देशिका का कराया सशपथ पाठन

विकसित व आत्मनिर्भर भारत के लिए हर देशवासी पंचप्रणों के साथ जुड़ें

हर भारतवासी के घर में संविधान की प्रति होनी चाहिए

लखनऊ। संविधान दिवस के अवसर पर लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान की उद्देशिका का सशपथ पाठन कराया। इसके पूर्व अतिथियों ने भारत

माता व बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के चित्र पर पुष्पार्चन किया। इस दौरान लघु फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया। संविधान दिवस के अवसर पर बुधवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से 2015 से पूरा देश प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करता है।

चुनाव के उपरांत गठित संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनी संविधान सभा ने अलग-अलग कमेटियां बनाई थीं, उसकी ड्रॉफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। योगी ने कहा कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान निर्माण में जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने योगदान व विशेषज्ञों ने सहयोग किया, उसी का परिणाम है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और भारत की अनेकता को एकता में जोड़ने वाला है। संविधान की मूल प्रति को लेकर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की समिति जब संविधान सभा के पास गई थी तब भी उन्होंने कहा था कि संविधान एक दस्तावेज है, जो भारत की विविधता को एकता में जोड़ने में मार्गदर्शिका के रूप में देश को नेतृत्व प्रदान करेगी।

योगी ने कहा कि आज हर संस्था, पंचायत में ऐसे आयोजन करके संविधान की प्रस्तावना का वाचन करने का प्रयास हुआ है। 2015 में संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने कहा था कि हममें से हर व्यक्ति स्वतंत्र भारत का नागरिक है, लेकिन स्वतंत्रता की वास्तविक कीमत विस्मृत की जा रही है। क्योंकि हमने स्वाधीनता की लड़ाई को आंखों से नहीं देखा। हमने क्रूर यातनाओं को नहीं सहा। परिणामस्वरूप हर व्यक्ति केवल अधिकार की बात करता है। अधिकार तब सुरक्षित होते हैं, जब व्यक्ति कर्तव्यों के निर्वहन की आदत डाले। कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं हो सकता। जहां कर्तव्य के बिना अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, वहां पर लोकतंत्र नहीं है, बल्कि वहां तानाशाह, व्यवस्था को गिरफ्त में लेकर आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रौंदते दिखते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान लागू होने के बाद भारत ने इसे सर्वोपरि मानकर सम्मान दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व प्रतीकों को सम्मान दिया और जिन मूल भावनाओं पर भारत का संविधान बना है, उसे जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास किया। जब कोई देश मूल भावनाओं को सम्मान देते हुए बढ़ता है तो उसे विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की संकल्पना रखी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रचंड जनसैलाब के अदम्य उत्साह के बीच 'सरदार@150 : राष्ट्रीय यूनिटी मार्च' का शुभारंभ कराया

करमसद से केवडिया तक 152 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के शुभारंभ अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, केन्द्रीय राज्य मंत्रियों श्रीमती अनुप्रिया पटेल एवं श्रीमती निमुबेन बांभणिया की विशेष उपस्थिति

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- 'सरदार पटेल@150 : यूनिटी मार्च' पदयात्रा राष्ट्रभक्ति का राजमार्ग प्रशस्त करेगी
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रेरित यह पदयात्रा सरदार पटेल को श्रेष्ठ श्रद्धांजलि है
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण का महाकार्य हो रहा है
- यह राष्ट्रीय पदयात्रा सरदार साहब के जीवन मूल्यों एवं आदर्शों को जानकर राष्ट्र निर्माण में सहभागी होने के लिए स्वर्णिम अवसर है
- देश में अनेक कल्याणकारी योजनाओं के सटीक क्रियान्वयन के कारण करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं
- यह पदयात्रा कोई साधारण पदभ्रमण नहीं; बल्कि देश की एकता, अखडंता एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक समान लौह पुरुष सरदार पटेल को समर्पित विशेष आयोजन है : त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा

(जीएनएस)।

गांधीनगर,26 नवंबर :प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से सरदार साहब की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित करमसद से केवडिया तक की

राष्ट्रीय पदयात्रा 'सरदार@150 : यूनिटी मार्च' को मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा ने फ्लैग ऑफ करके प्रस्थान कराया।

आणंद जिले के करमसद में प्रचंड जनसैलाब के अदम्य उत्साह तथा 'जय सरदार' के गगनभेदी नारों की गूंज के साथ यह राष्ट्रीय पदयात्रा आगामी 6 दिसंबर को सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुँचेगी।

150 स्थायी पदयात्रियों के साथ आणंद के अलावा वडोदरा तथा नर्मदा जिलों से गुजरने वाली इस पदयात्रा का भव्य शुभारंभ कराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सरदार@150 : यूनिटी मार्च' पदयात्रा राष्ट्रभक्ति का राजमार्ग प्रशस्त करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रेरित यह पदयात्रा सरदार पटेल को श्रेष्ठ श्रद्धांजलि है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने संविधान दिवस के अवसर पर डॉ. बाबासाहब आंबेडकर तथा संविधान सभा के सभी सदस्यों को आदरपूर्वक नमन करते हुए कहा कि विश्व नेता तथा 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के प्रेरणास्रोत श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में सरदार साहब की 150वीं जयंती भव्य रूप से मनाने का आयोजन हुआ है। इसी उपक्रम में जहाँ सरदार साहब का बचपन बीता था और जहाँ उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई थी, उस पवित्र भूमि करमसद से एकता के प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी-केवडिया तक यह यूनिटी मार्च आयोजित हो रही है।

मुख्यमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लौह पुरुष सरदार पटेल को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि बताते हुए कहा कि सरदार साहब की यह अभूतपूर्व प्रतिमा विश्वभर में भारत के सामर्थ्य एवं गौरव के इतिहास का जीवंत प्रतीक बनी है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि सरदार साहब ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के रूप में 562 देसी रजवाड़ों का विलय कर अखंड भारत का निर्माण किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरदार साहब के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार साहब द्वारा दिए गए राष्ट्रीय एकता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य के साथ यह यूनिटी मार्च आयोजित हो रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस पदयात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रमों से लोग सरदार साहब के जीवन मूल्यों को जानेंगे तथा राष्ट्रीय एकता का भाव अधिक सुदृढ़ होगा।

उन्होंने सरदार साहब के मूल्यों के आधार पर नए भारत के निर्माण का महाकार्य हो रहा होने का उल्लेख करते हुए जोड़ा कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक राम मंदिर में श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से ध्वजारोहण के साथ मंदिर निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। कुछ दिन पहले देश की श्रम शक्ति का सम्मान करने वालीं ऐतिहासिक चार श्रम संहिताएँ देश में लागू हुई हैं।

टकराव टालने के लिए 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक, विपक्ष के साथ अहम विधेयकों पर होगी चर्चा

(जीएनएस)।

संसद के पिछले सत्र में जमकर हंगामा हुआ था और कार्यवाही बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। मानसून सत्र में दोनों ही सदन चलाने में काफी व्यवधान हुआ था। सत्र के दौरान लगातार हंगामा और अवरोध चलता रहा। इस स्थिति को सुधारने और आगामी शीतकालीन सत्र को व्यवस्थित ढंग से चलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिस की है। 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।

परंपरा के मुताबिक, सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। संसद सत्र से ठीक पहले सरकार सभी दलों के नेताओं के साथ संवाद स्थापित कर राजनीतिक सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। एएनआई के सूत्रों के अनुसार, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

- यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब सत्र के दौरान पहले की तरह बार-बार हंगामे की आशंका जताई जा रही है। वोटर लिस्ट संशोधन, न्यूक्लियर एनर्जी बिल, उच्च शिक्षा सुधार बिल जैसे मुद्दों पर जमकर हंगामा हो सकता है।

- सरकार चाहती है कि इस बार संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले और सभी महत्वपूर्ण विधेयकों पर सार्थक चर्चा हो। इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है।

यह भी पढ़ें: ह्वल्ल३ी१ रीर२२्रङ्मल्लः शीतकालीन सत्र में सरकार लाएगी ये 10 नए बिल, न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर इन विधेयकों पर रहेगी नजर

- संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से आरंभ होने जा रहा है। इस बार सरकार लगभग 10 नए विधेयक (बिल) पेश करने की योजना बना रही है।

- इनमें सबसे अहम माना जा रहा है 'परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025', जो भारतीय परमाणु क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव की राह खोल सकता है।

सर्वदलीय बैठक में सरकार विपक्ष से सहयोग का आग्रह कर सकती है, ताकि सत्र के दौरान संसद गरिमापूर्ण ढंग से कार्य कर सके। पिछले सत्रों में कई बार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा बाधित रही है। इसलिए केंद्र सरकार पूरे सत्र को शांतिपूर्ण और सुचारू बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। शीतकालीन सत्र से पहले बुलाई गई यह बैठक तय करेगी कि क्या सभी दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बिना बाधा आगे बढ़ाने पर सहमत होते हैं या नहीं।

महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस को भाजपा ने दिया तगड़ा झटका

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य दल जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली भाजपा निकाय चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीत कर स्थानीय स्तर पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी के तहत भाजपा ने विपक्षी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तगड़ा झटका दिया है।

विधानसभा चुनाव में धराशायी हुए महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस और ठाकरे की शिवसेना के दो दिग्गज नेताओं ने बगावत कर भाजपा का दामन थाम लिया है।

नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के प्रचार अभियान के बीच, कोपरगांव के कांग्रेस शहर अध्यक्ष तुषार पोटे ने भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने अपने शहर अध्यक्ष पद और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

इसके साथ ही, शिवसेना (ठाकरे गुट) को भी नुकसान हुआ है। तुषार पोटे के साथ, शिवसेना (ठाकरे गुट) के पदाधिकारी कलविंदर दयाल भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस बीच, भाजपा के लोकतांत्रिक गठबंधन ने अपना नगर विकास घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है।

टीवी9 मराठी की रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी को मिली हार के बाद कई नेता महायुति में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे। निकाय चुनाव से पहले ये नेता भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। भाजपा में अन्य दलों के नेताओं का लगातार आना देखा जा रहा है।

शिंदे की शिवसेना छोड़ भाजपा में शामिल हुए कई नेता

इतना ही नहीं स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर सबसे बड़ा असर भाजपा की सहयोगी शिवसेना (शिंदे गुट) पर पड़ा है। शिवसेना (शिंदे गुट) के कई नेता और पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिससे शिंदे गुट में नाराजगी है। कई जगहों पर नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) आमने-सामने दिख रहे हैं।

महाराष्ट्र में कब है निकाय चुनाव?

नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान 2 दिसंबर को निर्धारित है, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इसके तुरंत बाद, राज्य में जिला परिषद, पंचायत समिति और नगरपालिका चुनाव होने की उम्मीद है।

तीन ट्रेनों का दिसंबर 2025 से वडोदरा मंडल के स्टेशनो पर अतिरिक्त ठहराव

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं मांग को ध्यान में रखते हुए वडोदरा मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर तीन ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. 10 दिसंबर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19019 बांद्रा टर्मिनस–हरिद्वार एक्सप्रेस चांपानेर रोड और खरसालिया स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन का चांपानेर रोड स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 07:18 बजे/07:19 बजे तथा खरसालिया स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 07:48 बजे/07:49 बजे होगा। इसी तरह, 10 दिसंबर, 2025 को हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19020 हरिद्वार–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस खरसालिया और चांपानेर रोड स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन खरसालिया स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 13:01 बजे/13:02 बजे तथा खरसालिया स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 13:20 बजे/13:21 बजे होगा।

2. 01 दिसंबर, 2025 को अहमदाबाद से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19418 अहमदाबाद–बोरीवली एक्सप्रेस बाजवा स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन 02:27 बजे बाजवा स्टेशन पहुंचेगी और 02:29 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

मुंबई, पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से 03 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित किए गए हैं।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः

ट्रेन संख्या 09007/09008 वलसाड – खातीपुरा (साप्ताहिक) स्पेशल

ट्रेन संख्या 09007 वलसाड – खातीपुरा स्पेशल के फेरों को 25 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09008 खातीपुरा – वलसाड स्पेशल के फेरों को 26 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09575/09576 राजकोट – महबूबनगर (साप्ताहिक) स्पेशल

ट्रेन संख्या 09575 राजकोट – महबूबनगर स्पेशल के फेरों को 29 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09576 महबूबनगर – राजकोट स्पेशल के फेरों को 30 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09520/09519 ओखा – मदुरै (साप्ताहिक) स्पेशल

ट्रेन संख्या 09520 ओखा – मदुरै स्पेशल के फेरों को 29 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09519 मदुरै – ओखा स्पेशल के फेरों को 02 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09007, 09575 एवं 09520 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 29 नवम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

'एक राष्ट्र, एक कर' ने देश भर में कर ढांचे को सरल और अधिक पारदर्शी बना दिया है: लोक सभा अध्यक्ष

सिविल सेवाओं में महिला अधिकारियों की बढ़ती संख्या भारत के विकास और आकांक्षाओं को दर्शाती है: लोक सभा अध्यक्ष

लोक सभा अध्यक्ष ने संसद भवन परिसर में भारतीय राजस्व सेवा (सी एंड आईटी) के 76वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों (ओटी) को संबोधित किया

(जीएनएस)।

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज कहा कि "एक राष्ट्र, एक कर" तथा जीएसटी ढांचे के साथ-साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधारों ने देश के कर ढांचे को सरल और अधिक पारदर्शी बना दिया है, जिससे भारत के विकास और समृद्धि में योगदान मिल है। उन्होंने कहा कि इस पारदर्शी व्यवस्था को बनाए रखने और इसे मजबूती प्रदान करने की जिम्मेदारी राजस्व सेवा के अधिकारियों की है।

श्री बिरला ने भारतीय राजस्व सेवा (सी एंड आईटी) के 76वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की, जो संसद भवन परिसर में संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) द्वारा आयोजित संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं के संबंध में आयोजित एक परिबोधन कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

विभिन्न केन्द्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री बिरला ने कहा कि महिला अधिकारियों की बढ़ती संख्या भारत के विकास और आकांक्षाओं को दर्शाती है।

श्री बिरला ने आज के युवाओं के तकनीकी कौशल और तकनीकी ज्ञान की भी प्रशंसा की, जो राष्ट्र निर्माण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार का लाभ उठाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा प्रशिक्षु अधिकारियों का साहसिक, आत्मविश्वास से युक्त और नया दृष्टिकोण भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर करने में सहायक होगा। उन्होंने आगे कहा कि युवा प्रशिक्षु अधिकारियों का योगदान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित "विकसित भारत" के लक्ष्य को सार्थक रूप से साकार करने में सहायक होगा।

इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, श्री बिरला ने कहा कि भारत की संसद देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नीति-निर्माण का केंद्र है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारीगण भारत की आर्थिक मजबूती के प्रमुख स्तंभ बनेंगे।

श्री बिरला ने कहा कि आईआरएस अधिकारी न केवल कर संग्रह करते हैं, बल्कि ईमानदार करदाताओं का सम्मान करने, व्यापार को सुगम बनाने, अवैध व्यापार और धन शोधन को रोकने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने इस बात को दोहराया कि सरकार का लक्ष्य कर प्रणाली को सरल और सुगम बनाना है ताकि नागरिक राष्ट्र के विकास और समृद्धि से जुड़ाव महसूस करें। इस संबंध में, सरकार का बृहत्तर लक्ष्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना और ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जहाँ करों की वसूली पूर्णतः कानून के अनुसार हो। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

श्री बिरला ने कहा कि डिजिटल कर प्रणाली, एआई-आधारित मूल्यांकन एवं डेटा विश्लेषण जैसे आधुनिक उपकरण कराधान में पारदर्शिता और निष्पक्षता को और बढ़ाते हैं। उन्होंने युवा प्रशिक्षु अधिकारियों से अपनी कड़ी मेहनत, क्षमता और नवाचार के माध्यम से योगदान देने का आ'ान किया। उन्होंने अधिकारियों को कराधान संबंधी कानूनों, संसदीय वाद-विवादों और हाल के कानूनों का गहन अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे कानून की मूल भावना को समझ सकें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवा आईआरएस अधिकारियों का यह समूह अपनी लगन, क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता से भारत के कर प्रशासन को और मजबूत करेगा तथा देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आईआरएस-सी एंड आईटी के 76वें बैच में 79 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल हैं, जिनमें 5 भूटान से हैं। इस बैच में 40% महिलाएँ हैं; 32% प्रशिक्षु अधिकारी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। बैच की औसत आयु 28 वर्ष है, और 51 प्रशिक्षु अधिकारी के पास पूर्व कार्य अनुभव है।

इस अवसर पर लोक सभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने स्वागत भाषण दिया।

धमेंद्र की प्रार्थना सभा में भावुक हुए सनी, बॉबी देओल, अभिषेक-ऐश्वर्या साथ आए नजर

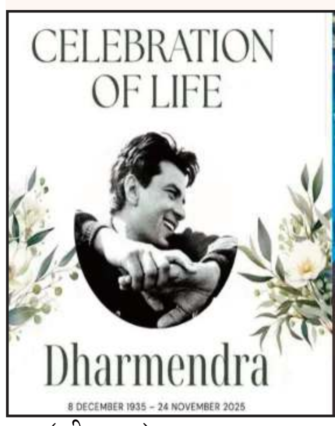

(जीएनएस)।

अभिनेता धर्मेंद्र देओल के निधन के बाद 27 नवंबर 2025 को मुंबई के एक आलीशान होटल में प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर देओल परिवार के अलावा बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां श्रद्धांजलि देने पहुंचीं। प्रार्थना सभा में बेटे सनी देओल, बॉली देओल बेहद भावुक नजर आए। वहीं सलमान खान जिन्हें धर्मेंद्र अपने तीसरे बेटे मानते थे वो काफी उदास दिखे।

धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में एक्ट्रेस रेखा, शाहरुख खान, आर्यन खान, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, टाइगर श्रॉफ, मलाइका अरोड़ा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनू सूद, रणदीप हुड्डा, मुकेश खन्ना, सोहा अली खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, नेहा धूपिया, अंगद बेदी और जैकी श्रॉफ जैसे सितारे शामिल थे। गायक सोनू निगम ने भी धर्मेंद्र के कुछ प्रतिष्ठित और प्रिय गीत गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण उन्हें दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। सुधार के संकेत मिलने के बावजूद, उन्होंने 24 नवंबर को अंतिम सांस ली।

अभिषेक-ऐश्वर्या साथ आए नजर

धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में ऐश्वर्या राय और उनके पति अभिषेक बच्चन भी पहुंचे थे। दोनों के बीच संबंबधों में खटास और बढ़ी दूरियों की खबरों के बीच ये ऐसा मौका था जब दोनों एक साथ एक जगह पर नजर आए। करण जौहर भी प्रार्थना सभा में पहुंचे और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। इससे पहले, करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र को याद करते हुए इसे "एक युग का अंत" बताया था। रणदीप हुड्डा, सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा अपने पति जहीर इकबाल के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे।

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान सहित कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुई थीं। प्रार्थना सभा में भी सितारों का तांता लगा रहा। सनी देओल और बॉबी देओल को अपने पिता की प्रार्थना सभा में आए मेहमानों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते देखा गया। उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी सामने आई, जिसमें दोनों भाई भावुक नजर आ रहे थे।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गुजरात की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के संदर्भ में समीक्षा बैठक हुई

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी :-

- सड़कों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने अधिकारियों और ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश
- सड़कों के निर्माण और रिसर्फेसिंग में नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें
- राज्य में राजमार्गों पर यातायात के 35 फीसदी से अधिक भार के मद्देनजर एनएचएआई द्वारा राजमार्गों की समुचित मरम्मत और आवश्यकता पड़ने पर विस्तारीकरण के कार्य जारी रहने चाहिए : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
- मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद-मुंबई, राजकोट-गोंडल-जेतपुर और अहमदाबाद-उदयपुर हाईवे के प्रगतिरत कार्यों को तेजी से पूरा करने के मुद्दे पर चर्चा की
- मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने गुजरात में एनएचएआई के हाईवे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से 20 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत करने का आश्वासन दिया

(जीएनएस)।

गांधीनगर, 27 नवंबर : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गांधीनगर में गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अंतर्गत संपन्न एवं प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई।

केंद्रीय मंत्री ने इस बैठक में अधिकारियों और ठेकेदारों से साफ-साफ कहा कि यह अत्यावश्यक है कि सड़कों की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो तथा नागरिकों की सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और रिसर्फेसिंग के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि निर्धारित समयसीमा में सड़क निर्माण के सभी कार्य पूरे नहीं हुए और लापरवाही पाई गई, तो ठेकेदार को ब्लेकलिस्ट करने तक के कठोर कदम भी उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस बैठक की चचाओं के दौरान केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात का भार 35 फीसदी से अधिक रहता है, इस संदर्भ में एनएचएआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन राजमार्गों की समुचित मरम्मत होती रहे और आवश्यकता पड़ने पर विस्तारीकरण के कार्य भी जारी रहें।

उन्होंने विशेष रूप से, अहमदाबाद-मुंबई, राजकोट-गोंडल-जेतपुर और अहमदाबाद-उदयपुर, तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रगतिरत कार्यों को तेजी से पूरा करने की दिशा में भी केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखे गए मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए श्री नितिन गडकरी ने केंद्र सरकार की ओर से गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के तहत हाईवे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत करने का आश्वासन इस बैठक में दिया।

इस बैठक में एनएचएआई की ओर से गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत अब तक हुए कार्यों और आगामी समय में एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से शुरू की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के बारे में भी प्रेजेंटेशन दिया गया। साथ ही, गुजरात में स्थित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की मौजूदा स्थिति, सड़कों के कार्य कब तक पूरे होने चाहिए थे और अभी जो कार्य बाकी रह गए हैं उन्हें कब तक पूरा कर लिया जाएगा, इन सभी विषयों पर गहन चर्चा की गई।

मुख्य सचिव श्री एम.के. दास ने गुजरात सरकार द्वारा हाईवे और सड़कों के प्रगतिरत कार्यों और केंद्र सरकार के साथ समन्वय की जानकारी दी।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया और सलाहकार श्री एस.एस. राठौर, अपर मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों के साथ-साथ मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, सचिव डॉ. विक्रांत पांडे और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और गुजरात सरकार के सड़क विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग डिविजन सहित संबद्ध विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

आईएएस अनुष्का शर्मा कौन हैं? बिना कोचिंग क्रैक किया यूपीएससी, अब सीएम योगी ने दी बड़ी जिम्मेदारी

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश सरकार में एक नई सितारा उभर रही हैं – आईएएस अनुष्का शर्मा। 26 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें प्रतापगढ़ जिले में संयुक्त मजिस्ट्रेट (जेएम) की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। यह नियुक्ति हाल के आईएएस तबादलों के तहत की गई है, जहां अनुष्का को जिले के प्रशासनिक मामलों, विकास योजनाओं और कानून-व्यवस्था की कमान संभालने का दायित्व दिया गया।

मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली यह युवा अधिकारी न सिर्फ अपनी मेहनत से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (वढरउ उरए 2022) में अखिल भारतीय रैंक (अक्क्र) 20 हासिल करने वाली हैं, बल्कि बिना किसी कोचिंग के सफलता पाने वाली प्रेरणा स्रोत भी। 23 मई 2023 को घोषित परिणामों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरने का मौका दिया। आइए, जानते हैं उनकी पूरी सफलता की कहानी...

अनुष्का शर्मा का जन्म राजस्थान के जयपुर में एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता सुनील शर्मा एक बैंक अधिकारी हैं, जिनका तबादला होता रहता था, जिससे परिवार को मुंबई, चंडीगढ़ और इंदौर जैसे शहरों में शिफ्ट होना पड़ा। इस घुमक्कड़ी ने अनुष्का को अनुकूलन की कला सिखाई। उन्होंने अपनी 10वीं कक्षा मुंबई से पूरी की, फिर दो साल चंडीगढ़ में पढ़ाई की। उच्च शिक्षा के लिए वे न्यूयॉर्क चली गईं, जहां सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की।

इंदौर में बस गए परिवार के साथ अनुष्का का मन हमेशा से भारत की विकास यात्रा से जुड़ना चाहता था। उनकी मां गृहिणी हैं, जो घर का मजबूत आधार रहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा बनीं उनकी चचेरी बहन हिमानी शर्मा, जो खुद एक आईएएस अधिकारी हैं। अनुष्का बताती हैं, 'हिमानी दीदी मेरी आइडल हैं। उन्होंने मुझे न सिर्फ सलाह दी, बल्कि तैयारी के दौरान किताबें और रणनीति साझा कीं।' यह पारिवारिक समर्थन ही था, जिसने अनुष्का को विदेश से लौटकर वढरउ का सफर शुरू करने का हौसला दिया।

UPSC की तैयारी अनुष्का के लिए कोई आसान रास्ता नहीं था। पिछले तीन साल से जुटे रहने के बाद तीसरे प्रयास में ही उन्हें सफलता मिली। पहले प्रयास में वे प्रीलिम्स क्लियर भी नहीं कर पाईं, जबकि दूसरे में इंटरव्यू तक पहुंचीं, लेकिन फाइनल लिस्ट से चूक गईं। हार मानना उनकी फितरत में नहीं था। उन्होंने कहा, 'मैं दृढ़ थी। असफलताओं से सीखा और आगे बढ़ी।'

सबसे खास बात – अनुष्का ने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया। पूरी तैयारी सेल्फ-स्टडी पर आधारित थी। उन्होंने टॉपर्स के इंटरव्यू से किताबों की लिस्ट बनाई, खासकर अर्थशास्त्र को वैकल्पिक विषय चुना क्योंकि यह उनकी ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से मेल खाता था। भूगोल और इतिहास जैसे विषयों के लिए संक्षिप्त नोट्स तैयार किए, जिन्हें नियमित दोहराती रहीं।

सीएम योगी का भरोसा, प्रतापगढ़ में नई शुरूआत

UPSC 2022 (जिसके परिणाम 2023 में आए) के बाद अनुष्का को उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित हुआ। हाल के तबादलों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें प्रतापगढ़ जिले में संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया। यहां उनकी भूमिका जिले के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, विकास परियोजनाओं को गति देने और जनता की समस्याओं का समाधान करने की होगी। प्रतापगढ़, जो प्रयागराज मंडल का हिस्सा है, अपनी सांस्कृतिक विरासत और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। अनुष्का की नियुक्ति से स्थानीय स्तर पर उत्साह है, क्योंकि उनकी युवा ऊर्जा और विदेशी एक्सपोजर जिले को नई दिशा दे सकता है।

अनुष्का कहती हैं, 'मैं भारत की विकास कहानी का हिस्सा बनना चाहती हूं। यह पोस्टिंग मेरे लिए चुनौती और अवसर दोनों है।' उनके आने से जिले में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं पर विशेष फोकस की उम्मीद है।

शौक और बैलेंसः संगीत, डांस से तरोताजा होतीं अनुष्का

UPSC की कठिन तैयारी के बीच अनुष्का ने खुद को मेंटली फिट रखने के लिए शौक अपनाए। उन्हें संगीत का शौक है – ब्रेक के दौरान वे क्लासिकल या लाइट म्यूजिक सुनतीं। डांस उनकी दूसरी सांस है। तैयारी के दौरान भी वे नियमित डांस और एक्सरसाइज करती रहीं। 'ये चीजें मेरे दिमाग को रिफ्रेश करती थीं,' वे बताती हैं। योग और मेडिटेशन भी उनकी रूटीन का हिस्सा रहे। यह बैलेंस ही उनकी सफलता का राज है – पढ़ाई के साथ जीवन का आनंद।

अनुष्का शर्मा प्रोफाइल एक नजर में

नामः अनुष्का शर्मा

यूपीएससी रैंकः AIR 20 (UPSC CSE 2022)

कैडरः उत्तर प्रदेश

वर्तमान पदः संयुक्त मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (UP)

जन्मस्थानः राजस्थान (परिवार अब इंदौर, मध्य प्रदेश में)

शिक्षाः अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन – सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क (अमेरिका)

तैयारी का तरीकाः पूरी तरह सेल्फ-स्टडी, बिना कोचिंग

प्रयासः तीसरा (पहले दो असफल)

तैयारी का समयः अक्टूबर 2019 से अप्रैल 2023 तक (लगभग 3.5 साल)

अनुष्का की पढ़ाई की स्ट्रैटेजी क्या थी?

रोज 8-10 घंटे पढ़ाई, प्रीलिम्स और मेन्स के करीब 13-14 घंटे

सोशल मीडिया और फालतू चीजों से पूरी तरह दूरी

टॉपर्स के नोट्स और सुझाई गई किताबों से ही पढ़ाई

कांसिस्टेंट रिवीजन – "हर टॉपिक को बार-बार दोहराती थी ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों"

मॉक टेस्ट और पिछले साल के पेपर खूब प्रैक्टिस किए

इंटरव्यू के लिए सिर्फ 8-10 घंटे ही काफी समझा

अनुष्का को मोटिवेशन कहां से मिला?

अनुष्का बताती हैं, 'मेरे परिवार में बैंकिंग सेक्टर में कई लोग हैं। वे गवर्नमेंट सेक्टर में देश की ग्रोथ में योगदान देते हैं, उनको देखकर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। मैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूं, इसलिए सिविल सर्विसेज चुना।'

बचपन का सपना नहीं था। 10वीं क्लास में सोशल साइंस की टीचर ने पहली बार कहा था कि मुझे इस फील्ड के बारे में सोचना चाहिए। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद यूनाइटेड नेशंस में 3 महीने की इंटर्नशिप की। वहां देखा कि पब्लिक पॉलिसी और इनक्लूसिव ग्रोथ कैसे काम करती है। उसी ने मुझे सिविल सर्विस की ओर खींचा।

प्रेरणा की मिसालः लाखों युवाओं के लिए संदेश

अनुष्का शर्मा की कहानी उन लाखों वढरउ एस्पिरेंट्स के लिए प्रेरणा है, जो कोचिंग के बिना सफल होना चाहते हैं। इंदौर से निकलकर अक्क्र20 हासिल करना और अब वढ के प्रतापगढ़ में जिम्मेदारी संभालना – यह साबित करता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और स्मार्ट प्लानिंग से कुछ भी संभव है। चचेरी बहन हिमानी की तरह, अनुष्का भी अब दूसरों को प्रेरित कर रही हैं। फैंस और साथी अधिकारी उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री 29-30 नवंबर को रायपुर में पुलिस महानिदेशकों/ महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे

सम्मेलन का विषयः 'विकसित भारतः सुरक्षा आयाम'

सम्मेलन में अब तक की प्रमुख पुलिस चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और 'सुरक्षित भारत' के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप तैयार की जाएगी

वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद का मुकाबला, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिसिंग में फोरेंसिक विज्ञान तथा एआई के उपयोग जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी

प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री 29-30 नवंबर, 2025 को भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ में पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन के 60वें संस्करण में भाग लेंगे।

यह सम्मेलन 28 से 30 नवंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य अब तक प्रमुख पुलिस चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा करना और 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप 'सुरक्षित भारत' के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप की रूपरेखा तैयार करना है।

'विकसित भारतः सुरक्षा आयाम' विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फोरेंसिक विज्ञान एवं एआई के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे।

यह सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। यह पुलिस बलों के सामने आने वाली परिचालन, अवसंरचनात्मक और कल्याण संबंधी चुनौतियों पर चर्चा के साथ-साथ अपराध से निपटने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पेशेवर प्रथाओं के निर्माण और साझाकरण को भी सुगम बनाता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस वार्षिक सम्मेलन में निरंतर गहरी रुचि दिखाई है, और स्पष्ट चचाओं को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार किया है जहां पुलिस व्यवस्था पर नए विचार उभर सकें। व्यावसायिक सत्र, विस्तृत बातचीत और विषयगत चचाएं प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा और नीतिगत मामलों पर सीधे प्रधानमंत्री के साथ अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान करती हैं।

वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में इस सम्मेलन के स्वरूप में निरंतर सुधार हुआ है, जिसमें देश भर के विभिन्न स्थानों पर इसका आयोजन भी शामिल है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

बीएलओ की मौतें और एसआईआर की अव्यावहारिक पर विपक्ष का जोर

देश के 12 राज्यों और वेंद्र शासित प्रादेशों में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के बीच बूथ लेवल अफसरों (बीएलओ) की मौत चिता का कारण बन गई है। मध्य प्रादेश में 24 घंटों में 2 बीएलओ की मौत हो गई है। वहीं पिछले 4 दिनों में भोपाल के 50 से ज्यादा बीएलओ बीमार पड़े हैं। इनमें दो को हार्ट अटैक और एक को ब्रेन हैमरेज हुआ है। दूसरी ओर पमि बंगाल में एक महिला बीएलओ ने तो आत्महत्या ही कर ली। परिजनों ने ज्यादा काम के दबाव को मौत का कारण बताया। एसआईआर 4 नवम्बर को शुरू हुआ। तब से अब तक यानि 19 दिनों में 6 राज्यों में 16 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात व मध्य प्रादेश में 4-4, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में 2, केरल व तमिलनाडु में 1-1 की जान गई है। पमि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनजा ने इन मौतों के लिए वेंद्र सरकार, चुनाव आयोग और भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनजा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एसआईआर को अव्यावहारिक बताते हुए इसे तुरन्त रोकने की मांग की है। कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रातिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने लिखा : एसआईआर के नाम पर देशभर में अफरा-तफरी मचा रखी है— नतीजा? तीन सालों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या एसआईआर में कोई सुधार नहीं। थोपा गया जुल्म है। उन्होंने आरोप लगाया, ईसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिक को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्वैन पन्नों को पलटना पड़े, मकसद साफ है——सही मतदाता हारकर थक कर बैठ जाए और वोट चोरी बिना रोक-टोक जारी रहे। दूसरी ओर भाजपा ने इन मौतों के लिए तृणमूल कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मुख्यालय वृष्णा नगर में बीएलओ के तौर पर काम करने वाली रिवू नामक महिला शिक्षक ने शनिवार को आत्महत्या कर ली। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शव के पास बरामद एक सुसाइड नोट में रिवू ने अपनी मौत के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज वुमार अग्रावाल ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए जिला चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस के मुताबिक रिवू ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उन्होंने 95 फीसदी ऑफलाइन काम पूरा कर लिया है, लेकिन ऑनलाइन के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। सुपरवाइजर को इस बारे में बताने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। इससे वुछ दिन पहले बर्धमान जिले के मेचारी में भी काम के कथित दबाव के कारण ब्रेन स्ट्रोक की वजह से नमिता हासंदा नाम का एक बीएलओ की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनजा ने इन घटनाओं पर दुख जताते हुए सवाल किया कि आखिर एसआईआर और कितने लोगों की जान लेगी? दूसरी ओर भाजपा और सीपीएम ने इन घटनाओं पर कहा था कि इनके लिए तृणमूल कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। सीपीएम नेता और पाटा के वेंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चव्रवता का सवाल है कि आखिर काम के दौरान बीएलओ को जान क्यों गंवानी पड़ रही है? उनका कहना था चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से इंकार नहीं कर सकता। साथ ही राज्य सरकार को भी बीएलओ की मदद करनी चाहिए थी। लेकिन सत्तारूढ़ पाटा और भाजपा इस प्राव्रिया का राजनीतिक फायदा उठाने में जुटी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राज्य में बीएलओ की मौतों और बीमारियों ने तृणमूल कांग्रेस को चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ एक मजबूत हथियार दे दिया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री और पाटा प्रामुख ममता बनजा इस मुद्दे पर लगातार दबाव बढ़ा रही हैं। राजनीतिक हानि-लाभ को एक तरफ रखें और इस दुखद मुद्दे पर विचार करें तो चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस दबाव के कारण आत्महत्या तक करने पर मजबूर होने की प्राव्रिया में सुधार लाना चाहिए या तो वह बीएलओ की संख्या बढ़ाएं या फिर लक्ष्य पूरा करने के लिए समय सीमा

कच्छ-सौराष्ट्र के कच्छी छुहारे और केसर आम से लेकर हस्तकला तथा हाथबुनाई काम के 10 से अधिक उत्पादों ने प्राप्त किया है जीआई टैग

गांधीनगर, 27 नवंबर : भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव देश के स्थानीय एवं वंश-परंपरागत उत्पादों पर ध्यान केन्द्रित किया है। स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देकर स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 'वोकल फॉर लोकल' अभियान की शुरूआत की है। उन्होंने 'वोकल फॉर लोकल' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अंतर्गत जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग वाले उत्पादों को सक्रिय प्रोत्साहन दिया है और इन उत्पादों को सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक सशक्तिकरण तथा वैश्विक मान्यता के साथ जोड़ा है। उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में भी बार-बार इन उत्पादों का उल्लेख किया है तथा कारीगरों को व्यक्तिगत रूप से जीआई सर्टिफिकेट प्रदान किए हैं।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 'विकास भी, विरासत भी' के विजन के साथ 2030 तक भारत में 10,000 जीआई (भौगोलिक संकेत) टैग वाले उत्पादों तक पहुँचने का लक्ष्य रखा है। जीआई टैगिंग जैसी पहल द्वारा राज्य के कारीगरों तथा किसानों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए गुजरात कच्छ के विख्यात कपड़े से लेकर सौराष्ट्र के प्रीमियम उत्पादों तक की अपनी विरासत को प्रमोट कर रहा है, जिससे राज्य वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भर बने। जीआई उत्पादों का संरक्षण तथा उनका प्रमोशन 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' के सिद्धांत पर बल देता है, जो स्थानीय क्षमताओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में परिवर्तित करता है।

कच्छ तथा सौराष्ट्र क्षेत्र ने अजरख, बांधणी (बंधेज), रोगन क्राफ्ट पेंटिंग, कच्छी शॉल, कच्छी छुहारा और केसर आम जैसे विख्यात उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त किए हैं, जो स्थानीय कारीगरों का विकास करते हैं और उन्हें वैश्विक पहचान देते हैं। राजकोट में आयोजित होने वाली आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) कच्छ-सौराष्ट्र के हस्तकला तथा हाथबुनाई कारीगरों की स्थानीय श्रेष्ठता एवं निर्यात संभावना को उजागर करने के लिए सज्ज है।

परंपरा तथा कलात्मकता से समृद्ध, गुजरात के कच्छ तथा सौराष्ट्र प्रदेशों ने उनकी सांस्कृतिक एवं कृषि विरासत को प्रस्तुत करने वाले उत्पादों के लिए 10 से अधिक जीआई मान्यताएँ प्राप्त की हैं। कच्छ के विख्यात उत्पादों में भरतकाम (कशीदाकारी), अजरख, ब्लॉक प्रिंटिंग, बांधणी टाई-डाई, रोगन क्राफ्ट पेंटिंग तथा कच्छी शॉल शामिल हैं। इसके अलावा; कृषि उत्पादों की बात करें, तो कच्छी छुहारे को भी जीआई टैग दिया गया है, जो उसके अद्भुत स्वाद एवं पोषक तत्वों से भरपूर गुणवत्ता के लिए विख्यात है। सौराष्ट्र के विशिष्ट उत्पादों में गीर का केसर आम, जो गीर प्रदेश में 'आम की रानी' के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है, जामनगरी बांधणी तथा राजकोट पटोळा रेशम बुनाई शामिल हैं। ये जामनगरी बांधणी तथा राजकोट की साड़ियाँ कई बॉलीवुड हस्तियों के वॉर्डरोब में भी स्थान पा चुकी हैं। इतना ही नहीं; सुरेन्द्रनगर की टांगलिया शॉल भी उसकी विशिष्ट वस्त्र कला का नमूना है, जिसने कला के उत्साहियों को आकर्षित किया है तथा एक वैश्विक मांग खड़ी की है।

सौराष्ट्र तथा कच्छ क्षेत्र में आयोजित होने वाली वीजीआरसी इस क्षेत्र की हस्तकला तथा हाथबुनाई कारीगरों की क्षमता को वेग देगी। यह दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस हेरिटेज क्षेत्र के उद्यमियों, कारीगरों, इंटीरियर डिजाइनर्स तथा प्रोडक्ट डिजाइनर्स के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस, निवेशकों, निजी उद्यमों तथा अग्रणी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग करने के लिए एक गतिशील प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा देती है, जो नवीनीकरण, बाजार पहुँच तथा टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देता है।

किसकी लगी करोड़ों में बोली और कौन रह गया अनसोल्ड? लिस्ट में कई हैरान करने वाले नाम!

(जीएनएस)।

महिला प्रीमियर लीग (हढछ 2026) का मिनी-ऑक्शन अब तक कई उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। टीमों ने अपनी रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खिलाड़ियों पर जमकर बोली लगाई। इस नीलामी में सबसे बड़ी खबर भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा से जुड़ी रही, जिन्हें यूपी वॉरियर्स ने 3.2 करोड़ की बड़ी कीमत पर खरीदकर उन्हें हढछ इतिहास की संयुक्त रूप से दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बना दिया।

ऑक्शन में यूपी वॉरियर्स का दबदबा

नीलामी में सबसे अधिक पर्स के साथ उतरी यूपी वॉरियर्स ने अभिषेक नायर के नेतृत्व में जबरदस्त खरीदारी की। दीप्ति शर्मा के अलावा यूपी ने किरण नवगिरे और इंग्लिश स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन को वापस टीम में लाने के लिए सफलतापूर्वक 'राइट-टू-मैच' कार्ड का इस्तेमाल किया। यूपी वॉरियर्स ने अपनी बल्लेबाजी को मजबूती देते हुए तीन बार की फाइनलिस्ट कप्तान मेग लैनिंग को 1.9 करोड़ में खरीदा। टीम ने सोफी डिवाइन (2 करोड़), रेणुका सिंह (60 लाख), और युवा प्रतिभा फीबी लिचफील्ड (1.20 करोड़) को भी खरीदकर अपनी टीम को संतुलित बनाया।

हढछ अ४ृ३ङ्गल्ल 1

मुंबई और दिल्ली की ऐसी रही खरीदारी

गत चैंपियन मुंबई इंडियंस (टक) ने अपने कोर को मजबूत करने पर ध्यान दिया। मुंबई ने न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर पर 3 करोड़ की बड़ी बोली लगाकर उन्हें नीलामी की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बनाया। उनके साथ मुंबई ने दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल (60 लाख) को भी अपनी टीम में शामिल किया।

वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज की गई श्री चरानी को वापस खरीदा और कप्तान मेग लैनिंग के जाने के बाद उनकी जगह दक्षिण अफ्रीका की विस्फोटक सलामी बल्लेबाज लॉरा वोलवाड्र्ट (1.1 करोड़) को लिया। दिल्ली ने चिनले हेनरी (1.30 करोड़) और भारतीय स्पिन ऑलराउंडर स्नेह राणा (50 लाख) को भी खरीदा।

बिके हुए खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

बिके हुए खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

एमिली केर, मुंबई इंडियंस - ₹3 करोड़

शबनीम इस्माइल, मुंबई इंडियंस - ₹60 लाख

संस्कृति गुप्ता, मुंबई इंडियंस - ₹20 लाख

लौरा वोल्वाड्र्ट, दिल्ली कैपिटल्स - ₹1.1 करोड़

चिनेल हेनरी, दिल्ली कैपिटल्स - ₹1.30 करोड़

श्री चरणी, दिल्ली कैपिटल्स - ₹1.30 करोड़

स्नेह राणा, दिल्ली कैपिटल्स - ₹50 लाख

लिजेल ली, दिल्ली कैपिटल्स - ₹30 लाख

दीया यादव, दिल्ली कैपिटल्स - ₹10 लाख

दीप्ति शर्मा, वढ वॉरियर्स - ₹3.2 करोड़

सोफी एक्लेस्टोन, वढ वॉरियर्स - ₹85 लाख

मेग लैनिंग, वढ वॉरियर्स - ₹1.9 करोड़

फोबे लिचफील्ड, वढ वॉरियर्स - ₹1.20 करोड़

किरण नवगिरे, वढ वॉरियर्स - ₹60 लाख

हरलीन देओल, वढ वॉरियर्स - ₹50 लाख

क्रांति गौड़, वढ वॉरियर्स - ₹50 लाख

आशा सोभना, वढ वॉरियर्स - ₹1.1 करोड़

सोफी डिवाइन, वढ वॉरियर्स - ₹2 करोड़

रेणुका सिंह, वढ वॉरियर्स - ₹60 लाख

भारती फुलमाली, वढ वॉरियर्स - ₹70 लाख

टिटस साधु, वढ वॉरियर्स - ₹30 लाख

जॉर्जिया वोल, वढ वॉरियर्स - ₹60 लाख

नादिन डी क्लर्क, वढ वॉरियर्स - ₹65 लाख

राधा यादव, वढ वॉरियर्स - ₹65 लाख

लॉरेन बेल, वढ वॉरियर्स - ₹90 लाख

लिंसे स्मिथ, वढ वॉरियर्स - ₹30 लाख

प्रेमा रावत, वढ वॉरियर्स - ₹20 लाख

फ्रीङ्गेल्ल्ीीि ऋङ्क१ ङ्ग४

<२३१ङ्गल्ल>ऑक्शन के बीच हढछ 2026 का शेड्यूल जारी, इस दिन शुरू होगा टूनार्मेट, फिर होगी चौके-छक्कों की बारि</२३१ङ्गल्ल>श!

ऑक्शन के बीच हढछ 2026 का शेड्यूल जारी, इस दिन शुरू होगा टूनार्मेंट, फिर होगी चौके-छक्कों की बारिश!

बिना बिके खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

50 हजार रुपये में फॉरेन ट्रिप, कौन-से देश हैं सबसे किफायती?

(जीएनएस)।

विदेश घूमने का सपना लगभग हर किसी का होता है, लेकिन बजट देखकर कई लोग अपना प्लान टाल देते हैं। सच यह है कि भारत के पास ऐसे कई देश हैं जहां आप उतने ही पैसे में विदेश यात्रा का मजा ले सकते हैं, जितने में देश के भीतर किसी बड़े शहर की ट्रिप होती है। इन जगहों की खास बात यह है कि यहां तक पहुंचना आसान है। फ्लाइट टिकट महंगे नहीं होते, रोजाना का खर्च कम आता है और रहने-खाने के भी किफायती विकल्प मिल जाते हैं।

यही कारण है कि नेपाल की शांत पहाड़ियां, भूटान का सुकून, थाईलैंड का समुद्री रोमांच, श्रीलंका के चाय बागान, वियतनाम की पुरानी गलियां, मलेशिया के आधुनिक शहर और लाओस का प्राकृतिक माहौल भारतीय यात्रियों के लिए शानदार और सस्ती छुट्टी का नया विकल्प बन गए हैं। कम समय में ज्यादा मजा लेने का ट्रेंड बढ़ रहा है और ऐसे में ये नजदीकी देश कम बजट में बेहतरीन विदेशी अनुभव देते हैं।

नेपाल

भारत के सबसे नजदीक बसे नेपाल में बिना वीजा प्रवेश मिल जाने से खर्च और भी कम हो जाता है। काठमांडू के पुराने मंदिर, भीड़भाड़ वाले बाजार और पोखरा की झीलों का सुकून कम पैसे में मिल जाता है। यहां रहने और खाने का खर्च काफी कम है, इसलिए बजट ट्रिप आराम से बन जाती है।

थाईलैंड

थाईलैंड भारतीय यात्रियों के बीच लगातार लोकप्रिय है। बैंकॉक का रंगीन माहौल, फुकेत के शांत समुद्र तट और सस्ता स्ट्रीट फूड इसे और भी अच्छा विकल्प बनाते हैं। यहां अक्सर कम दाम में फ्लाइट टिकट मिल जाते हैं और वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा भी पैसे बचाती है। समझदारी से होटल चुनें तो पूरी यात्रा 50,000 रुपये के अंदर हो जाती है।

भूटान

भूटान में कदम रखते ही शांति का अलग ही अहसास होता है। यहां ऊंचे पहाड़, रंगीन मठ और शांत घाटियां देखने को मिलती हैं। भारतीय नागरिक बिना वीजा यहां जा सकते हैं। अगर आप लोकल बसों से सफर करें और गेस्टहाउस में रुकें, तो यह ट्रिप कम पैसे में पूरा हो जाता है।

लाओस

लाओस भी बजट यात्रियों की पसंद बन रहा है। यहां नदी, झरने, जंगल और पुराने मंदिर काफी आकर्षित करते हैं। यहां का रोजाना का खर्च बहुत कम है, इसलिए 50,000 रुपये के अंदर घूमना मुश्किल नहीं होता। शांत माहौल चाहने वालों के लिए यह सबसे अच्छी जगह है।

श्रीलंका

भारत के पास बसे श्रीलंका में समुद्र तट, चाय बागान, किले और स्थानीय बाजार सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। यहां रहने, खाने और घूमने का खर्च काफी कम है।

सीमा हैदर पर एसआईआर प्रक्रिया का क्या होगा असर? नोएडा छोड़कर जाना होगा? क्या है निमय- अब वकील ने किया खुलासा

Intensive Revision यानी SIR अभियान ने कई राज्यों के साथ-साथ यूपी में भी हलचल मचा रखी है। लेकिन इस बीच चर्चा उस महिला को लेकर भी है, जिसका मामला पिछले दो साल से देशभर में सुर्खियों में है। नाम है सीमा हैदर। लोग सोशल मीडिया से लेकर लोकल लेवल पर सवाल पूछ रहे हैं कि रक्ष्क्र का असर क्या सीमा हैदर पर भी पड़ेगा। क्या वह नोएडा छोड़ने पर मजबूर होंगी और क्या यूपी सरकार या उट योगी आदित्यनाथ उनकी किसी तरह मदद कर सकते हैं।

सवाल वाजिब है क्योंकि रक्ष्क्र प्रक्रिया का मकसद सभी मतदाताओं का डेटा वेरिफाई करना, डुप्लीकेट या संदिग्ध एंट्री हटाना और 2002 की वोटर लिस्ट के आधार पर नागरिकता के दावों की जांच करना है। जबकि सीमा हैदर का पूरा मामला ही नागरिकता और कानूनी स्थिति पर टिका है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि रक्ष्क्र उनके केस को कितना प्रभावित करेगा।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने रक्ष्क्र वेरिफिकेशन को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि सीमा का मसला वोटर लिस्ट का नहीं बल्कि 'जीवनदान' का है। एपी सिंह के मुताबिक सीमा रक्ष्क्र के दायरे से ऊपर हैं क्योंकि यह मामला सीधे मानवीय आधार और राष्ट्रपति के पास लंबित याचिका से जुड़ा है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन इससे केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि सीमा कोई जासूस या आतंकी नहीं, बल्कि वह प्रेम के कारण भारत आई हैं। अगर कभी वह आतंकी निकलीं तो "डबल फांसी दे दीजिए।"

इस बयान के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका पक्ष रक्ष्क्र को सीमा के लिए गैर-चिंताजनक बता रहा है। लेकिन कानून क्या कहता है, यह भी समझना जरूरी है।

साफ शब्दों में कहा जाए तो नहीं। रक्ष्क्र अभियान सिर्फ मतदाता सूची अपडेट करने और नागरिकता दस्तावेजों की प्राथमिक जांच के लिए है। यह किसी भी व्यक्ति को घर छोड़ने या कहीं और जाने के लिए मजबूर नहीं करता। यह सिर्फ वोटर डेटा का सत्यापन है, न कि पुलिस या केंद्रीय एजेंसियों की नागरिकता जांच।

दूसरी बात सीमा खुद अवैध प्रवेश के केस में जमानत पर हैं और उनका मामला पहले से न्यायिक प्रक्रिया में है। इसलिए रक्ष्क्र उनके रहने, जाने, आने या लोकेशन को प्रभावित नहीं करता। हालांकि अगर सीमा ने कभी वोटर लिस्ट के लिए आवेदन किया हो, या किसी भारतीय पहचान दस्तावेज में नाम जुड़वाने की कोशिश की हो, तब रक्ष्क्र में सवाल जरूर उठ सकता है। लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है।

जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर को

संस्कृत के प्रचार-प्रसार और संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शुरू की गई 'योजना पंचकम्'

राज्य के 34 स्थानों पर प्रतिभागी गीता के श्लोक और संस्कृति सुभाषितों का पारायण करेंगे, भगवद् गीता पर व्याख्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन

गांधीनगर, 27 नवंबर : राज्य में संस्कृत भाषा और साहित्य के व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से प्राचीन भाषा संस्कृत को प्रोत्साहन देने और उसके संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड ने 'योजना पंचकम्' शुरू की है।

'योजना पंचकम्' में संस्कृत सप्ताह महोत्सव योजना, संस्कृत संवर्धन सहायता योजना, संस्कृत प्रोत्साहन योजना, श्रीमद् भगवद् गीता योजना और शत सुभाषित कंठपाठ योजना का समावेश किया गया है। इनमें से

भगवद् गीता योजना और शत सुभाषित कंठ पाठ योजना के तहत प्रतिभागियों को जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।

1 दिसंबर, 2025 को गीता जयंती के अवसर पर राज्य में जिला स्तर पर 34 स्थानों पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से इन योजनाओं के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा, श्रीमद् भगवद् गीता के अध्याय 12 और 15 का सामूहिक पारायण, लोगों के लिए संस्कृत प्रदर्शनी, भगवद् गीता पर व्याख्यान सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

आगामी समय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर संपूर्ण गीता कंठ पाठ योजना की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के दौरान श्रीमद् भगवद् गीता योजना और शत सुभाषित कंठ पाठ योजना में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के श्लोकों के उच्चारण और कंठ पाठ संबंधित श्लोकों के लय-छंद, उच्चारण की शुद्धता और कंठ पाठ की दक्षता के साथ ही भाव-भक्ति और आत्मविश्वास युक्त प्रस्तुति की समीक्षा की जाती है।

संयुक्ता शनमुगनाथन ने चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व क्रिकेटर अनिरुद्ध श्रीकांत से शादी कर ली

..

तमिल सिनेमा और बिग बॉस तमिल सीजन 4 की स्टार संयुक्ता शनमुगनाथन ने गुरुवार (27 नवंबर 2025) को चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व क्रिकेटर अनिरुद्ध श्रीकांत से शादी कर ली।

यह दोनों की दूसरी शादी है, जो पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के साथ उनके घर पर सादगी भरा समारोह था। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फैंस के सवालों का दौर शुरू हो गया - संयुक्ता किस जाति से हैं? उनकी पहली शादी क्यों टूटी? अनिरुद्ध का बैकग्राउंड क्या है? आइए, इन सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं...

संयुक्ता शान की जाति- नायर समुदाय से ताल्लुक

संयुक्ता शनमुगनाथन का जन्म एक मलयाली नायर परिवार में हुआ है। नायर जाति केरल की प्रमुख हिंदू समुदायों में से एक है, जो ऐतिहासिक रूप से क्षत्रिय वर्ग से जुड़ी हुई मानी जाती है। यह समुदाय योद्धा और भूमि मालिक वर्ग के रूप में जाना जाता रहा है और आज भी केरल और तमिलनाडु के मलयाली परिवारों में सम्मानित स्थान रखता है। संयुक्ता के पिता रमन नायर और माता प्रतीभा नायर - दोनों नायर समुदाय से हैं। उनका जन्म 31 दिसंबर 1985 को कोयंबटूर (तमिलनाडु) में मलयाली परिवार में हुआ, हालांकि वे चेन्नई में पली-बढ़ीं। यह शादी भी हिंदू परंपराओं के अनुसार हुई, जो दोनों परिवारों की सांस्कृतिक समानता को दर्शाती है।

अनिरुद्ध श्रीकांत की जाति- तमिल ब्राह्मण परिवार से

अनिरुद्ध श्रीकांत का जन्म 14 अप्रैल 1987 को चेन्नई में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता, क्रिकेट लेजेंड कृष्णमाचारी श्रीकांत, 1983 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान रहे और वे भी तमिल ब्राह्मण समुदाय से हैं। अनिरुद्ध के बड़े भाई आदित्य श्रीकांत भी क्रिकेटर हैं। यह परिवार चेन्नई के मायलापुर इलाके से जुड़ा है, जहां ब्राह्मण संस्कृति गहरी जड़ें रखती है।

अनिरुद्ध की पहली शादी मॉडल आरती वेंकटेश से 2012 में हुई थी, जो दो साल बाद 2014 में तलाक में खत्म हो गई। तलाक की सटीक वजह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह वैवाहिक असहमति के कारण हुआ। कोई बच्चे नहीं हैं।

संयुक्ता की पहली शादी क्यों टूटी? पति के अफेयर ने तोड़ा विश्वास

संयुक्ता की पहली शादी टेक उद्यमी कार्तिक शंकर से हुई थी, जिससे उनका एक बेटा रेयान है। यह रिश्ता 2025 की शुरूआत में तलाक के साथ खत्म हो गया। संयुक्ता ने खुद खुलासा किया कि कोविड महामारी के दौरान उन्हें पता चला कि उनके पति पिछले चार साल से किसी अन्य महिला के साथ रिश्ते में थे। इस धोखे ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'यह जानने के बाद लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी हुई थी।'

फरवरी 2025 में तलाक फाइनल होने के बाद संयुक्ता ने सोशल मीडिया पर ' पोस्ट-डिवोर्स ग्लो' वाली तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा - '2025 में कागजी कार्रवाई पूरी हो गई। अब और मजबूत हूं।' इस घटना ने उन्हें भावनात्मक रूप से तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने बेटे रेयान की परवरिश पर फोकस किया और करियर को नई दिशा दी। तलाक के नौ महीने बाद ही अनिरुद्ध से शादी ने उनकी जिंदगी में नई शुरूआत की है।

संयुक्ता का पारिवारिक और व्यक्तिगत बैकग्राउंड

संयुक्ता का परिवार मलयाली मूल का है, लेकिन वे तमिलनाडु में बसे हुए हैं। उनके पिता शनमुगनाथन नायर एक बिजनेसमैन हैं, जबकि मां प्रतीभा नायर गृहिणी। उनके एक बड़े भाई हैं, जिनके बारे में ज्यादा सार्वजनिक जानकारी नहीं है।

मैक्स हॉस्पिटल, लखनऊ के डॉक्टरों की दुर्लभ बाइल डक्ट स्टोन सर्जरी से दिल्ली के युवक को मिला नया जीवन

एलआर

लखनऊ, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ के डॉक्टरों ने हेपेटोलिथाइसिस के एक असामान्य और अत्यंत जटिल मामले का सफल उपचार कर एक बेहतरीन चिकित्सकीय उपलब्धि हासिल की है। हेपेटोलिथाइसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिवर की छोटी पित्त की नलियों के अंदर गहराई में पथरी बन जाती है। दिल्ली निवासी 27 वर्षीय मरीज, ऋषभ सिंह लगातार और परेशान करने वाले लक्षणों जैसे बार-बार तेज बुखार, पीलिया, पेट में दर्द और तेजी से वजन घटने जैसी समस्याओं के साथ मैक्स हॉस्पिटल, लखनऊ पहुंचे। शुरूआती जांच से पता चला कि वह बार-बार होने वाली पायोजेनिक कोलेंजाइटिस से पीड़ित थे, एक ऐसी पुरानी बीमारी जिसमें पित्त की नलिओं में बार-बार संक्रमण और सूजन होती है, जो समय रहते इलाज न मिलने पर पथरी बनने और गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है। युवाओं में हेपेटोलिथाइसिस के साथ बार-बार होने वाली पायोजेनिक कोलेंजाइटिस का मिलना

बहुत असामान्य है और लिवर के अंदर गहराई में स्थित पथरियों के साथ सक्रिय संक्रमण होने से इस मामले की जटिलता अधिक हो जाती है। मरीज ने इससे पहले एक अन्य अस्पताल में इलाज के लिए प्रोसीजर करवाया था पर वह सफल नहीं हुआ। इसके बाद उनकी सेहत लगातार खराब होती रही और वजन भी घटता रहा। इस मामले में, मैक्स हॉस्पिटल, लखनऊ में हेपेटो-पैंक्रिएटो-बिलियरी एवं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के निदेशक, डॉ. वलीउल्लाह सिद्दीकी ने कहा, 'जब ऋषभ हमारे पास आए, वह पहले से ही लगातार वजन घटने और बार-बार होने वाले संक्रमणों का सामना कर रहे थे। गहराई से की गई जाँच में बार-बार होने वाले पायोजेनिक कोलेंजाइटिस के साथ लिवर में कई पथरियां पाई गईं। चुनौती गम्भीर थी, जिसे संभालने के लिए अत्यंत सावधानीपूर्वक और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच की आवश्यकता थी।' इलाज के लिए, सर्जिकल टीम ने एक जटिल लिवर सर्जरी की, जिसमें लिवर के बाएं हिस्से को (जहां कई पथरियां थीं) हटाया गया, लिवर के बाहर की क्षतिग्रस्त पित्त नली को निकालकर उसके दाहिने हिस्से और आंत के बीच एक नया जोड़ बनाया गया, ताकि पित्त का बहाव सामान्य रूप से हो सके। डॉ. सिद्दीकी ने आगे कहा कि सर्जरी तकनीकी रूप से बहुत जटिल थी, लेकिन ऋषभ ने असाधारण रूप से अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उनकी रिकवरी सहज रही और उन्हें ऑपरेशन के आठवें दिन छुट्टी दे दी गई। एक महीने के फॉलोअप में उनकी स्थिति में बढ़िया सुधार दिखा, लक्षण पूरी तरह खत्म हो गए और वह सामान्य रिकवरी पैरामीटर पर लौट आए। इस सफल नतीजे के लिए मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ की असामान्य और जटिल हेपेटोबिलियरी स्थितियों को संभालने की क्षमता, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ज़िम्मेदार है।

बैटरी स्मार्ट ने इम्पैक्ट रिपोर्ट 'रीडिफाइनिंग मोबिलिटी वन ईवी एट ए टाइम जारी की

एलआर

लखनऊ। भारत के स्वच्छ यातायात अभियान के प्रति अपना वचनबद्धता दोहराते हुए बैटरी स्मार्ट ने अपनी पहली इम्पैक्ट रिपोर्ट'रीडिफाइनिंग मोबिलिटी, वन ईवी एट ए टाइम' का अनावरण किया है। बैटरी स्मार्ट इलेक्ट्रिक दो-पहिया और तीन-पहिया वाहनों के लिए भारत का सबसे बड़ा बैटरी-स्वैपिंग नेटवर्क उपलब्ध कराती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे कंपनी का पार्टनर मॉडल भारत के ईवी परिदृश्य को बदल रहा है, कार्बन उत्सर्जन कम करने को बढ़ावा देकर, समावेशी समृद्धि सुनिश्चित करके, और एक टिकाऊ, और एक टिकाऊ, टेक-समर्थित ऊर्जा इकोसिस्टम बनाकर। रिपोर्ट साझा करते हुए बैटरी स्मार्ट के को-फाउंडर और सीईओ पुलकित खुराना ने कहा, 'यह रिपोर्ट बैटरी स्मार्ट का सफर दिखाती है। साथ ही

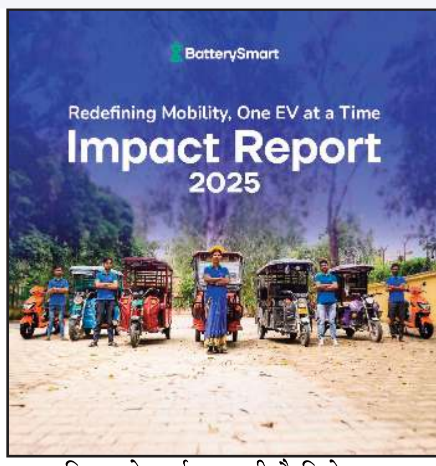

उस परिदृश्य के दर्शन कराती है जिसे हमने अपने ड्राइवरों, साझेदारों और हितधारकों के साथ मिलकर बनाया है ताकि भारत का ईवी क्षेत्र गति पकड़ सके। आज यह प्रयास एक स्केलेबल, टेक्नोलॉजी-लेड समाधान बन गया है जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सस्ता, आसान और समावेशी बनाता है। यह रिपोर्ट एक अहम पड़ाव है क्योंकि हम नए बाजारों में आगे बढ़ रहे हैं, अपना असर बढ़ा रहे हैं और भारत के नेट-जीरो लक्ष्यों में अहम योगदान दे रहे हैं। जानी-मानी सस्टेनेबिलिटी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन कंपनी टीयूवी एसयूडी ने इस रिपोर्ट का पुष्टि किया है। इस रिपोर्ट में कंपनी के पर्यावरण की देखभाल, सामाजिक सशक्तिकरण और जिम्मेदार प्रबंधन में योगदान की जानकारी दी गई है। यह भारत के क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन को गति देने की उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दिखाता है। भविष्य में बैटरी स्मार्ट का लक्ष्य 2026 तक 100 शहरों तक विस्तार करना, ज्यादा प्ओटी-इनेबल्ड बैटरी लगाना और सुरक्षा, इनोवेशन और सकुर्लेरिटी को और मजबूत करना हैकृताकि देश भर में एक मजबूत ईवी इकोसिस्टम बनाया जा सके।

शिकायत चाहे करो हजार, ग्राम प्रधान के नहीं पाओगे पार, यह है ग्राम पंचायत आगापुर दबंग प्रधान की ललकार के आगे नतमस्तक

(जीएनएस)।

लखनऊ। हरदोई की ब्लाक शाहाबाद की ग्राम पंचायत आगापुर में लाखों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने शिकायती पत्र उच्च अधिकारियों को कई बार दिए लेकिन जांच तो दूर की बात शिकायत पर अधिकारियों ने सज्ञान तक नहीं लिया ग्राम सरदारनगर के निवासी सत्यवीर सिंह, रामवीर सिंह, मनोज कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे गांवों में मार्च 25 में नाली की मरम्मत ग्राम प्रधान अखिलेश कुमार के द्वारा करायी गई थी जिसमें मात्र 6 बोरी सीमेंट और 10 कुन्टल मौरंग 1 हजार ईंट लगाई गई थी जिसका कुल पैसा 1 लाख 38 हजार रुपये ग्राम प्रधान ने ब्लाक के बीडीओ और कर्मचारियों की सह से निकाल लिया जिला प्रशासन बताये कि उक्त मैटेरियल कितने का होगा ऐसे कई घोटाले किए हैं। ग्राम पंचायत के

निवासी अजीत कुमार ने बताया कि हम से 20 हजार रुपये मांग करी जिसको हमने नहीं दे पाए उसके बाद में मेरा आवास प्रधान द्वारा कटवा दिया गया इसी ग्राम पंचायत के छोटेलाल ने कहा कि बहुत से लाभार्थियों पर पैसा लिया गया उसके बाद में आवास बनवाये गए अजीत कुमार का आज भी कहना है कि बहुत से प्रर्थना पत्र हमने दिए और जवाब पूछा कि हमरा आवास क्यूँ काटा गया किसी भी अधिकारी ने जवाब नहीं दिया बिना काम किए अपने ही चहतों के खातों में डाले लाखों रुपये ग्राम पंचायत के निवासी सत्यपाल, राम स्वरूप का कहना है कि अपने भाई रजनीश कुमार, अपने चाचा पंकज कुमार, अजय भारती सहित कई लोगों के खातों में ग्राम प्रधान ने मनरेगा सहित ग्राम निधि से 4 साल में लाखों रुपये डाले जिसकी रिकवरी के लिए किसान नेता सत्यवीर सिंह ने सभी स्क्रीन शाट लगाकर मांग की लेकिन अधिकारी नहीं आये पुराने बने शौचालयों पर निकाल दिए पैसे गांव के निवासी सुशील कुमार, मोहित कुमार, नरेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार ने बताया कि हमारे गाँव के प्रधान ने शौचालय पहले के प्रधान द्वारा बनाए गए थे उन्हीं लोगों को पैसा खाते पर डालकर आधे-आधे बांट लिए और शौचालय पूर्व के बने दिखा दिए इसकी जांच करके कार्यवाही की जाये नलों की मरम्मत सहित रिवोर में भी की हेरा फेरी ग्राम पंचायत के निवासी शिवओम, संतराम, राजेश का कहना है कि हमारे यहां नल के रिवोर 6 माह में कराए जाते हैं यहां तक मरम्मत के भी लाखों रुपये निकाल कर 4 पहिया गाड़ी से फरार्टे भरते नजर आ रहे हैं कोई भी अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहा है इसलिए प्रधान का कहना है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा।

ट्राई ने अक्टूबर माह के दौरान दिल्ली में नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया

(जीएनएस)।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिल्ली लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के लिए अपने स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) के निष्कर्ष जारी किए है, जिसमें अक्टूबर 2025 के दौरान शहर के व्यापक मार्गों को शामिल किया गया। ये ड्राइव परीक्षण विभिन्न उपयोग वातावरणों – शहरी क्षेत्रों, संस्थागत हॉटस्पॉट, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों और हाई-स्पीड कॉरिडोर में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए ट्राई क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली की देखरेख में आयोजित किए गए थे।

ट्राई की टीमों ने 6 अक्टूबर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 के बीच , 402.0 किलोमीटर के सिटी ड्राइव टेस्ट, 14 हॉटस्पॉट स्थानों, 6.1 किलोमीटर के वॉक टेस्ट और 01 स्थान पर इंटर ऑपरेटर कॉलिंग के विस्तृत परीक्षण किए। मूल्यांकन की गई तकनीकों में 2 जी, 3 जी, 4 जी और 5 जी नटवर्क शामिल थे, जो विभिन्न हैंडसेट क्षमताओं वाले उपयोगकताओं के सेवा अनुभव को दशार्ते हैं। स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट के निष्कर्षों से सभी संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को पहले ही अवगत करा दिया गया है।

मूल्यांकित प्रमुख पैरामीटरः

) वॉयस सेवाएं : कॉल सेटअप सफलता दर (सीएसएसआर), ड्रॉप कॉल दर (डीसीआर), कॉल सेटअप समय, कॉल साइलेंस दर और स्पीच क्वालिटी (एमओएस) कवरेज।

ख) डेटा सेवाएं : डाउनलोड/अपलोड थ्रूपुट, विलंबता, जिटर, पैकेट ड्रॉप दर और वीडियो स्ट्रीमिंग विलंब।

कॉल सेटअप सफलता दरः एयरटेल, एमटीएनएल, आरजेआईएल और वीआईएल की ऑटो-सिलेक्शन मोड (5 जी/4 जी/3 जी/2 जी) में कॉल सेटअप सफलता दर क्रमशः 99.50 प्रतिशत , 86.53 प्रतिशत , 99.30 प्रतिशत और 98.59 प्रतिशत है।

ड्रॉप कॉल दरः एयरटेल, एमटीएनएल, आरजेआईएल और वीआईएल में ऑटो-सिलेक्शन मोड (5 जी/4 जी/3 जी/2 जी) में ड्रॉप दर क्रमशः 0.00 प्रतिशत , 7.46 प्रतिशत , 0.00 प्रतिशत और 0.20 प्रतिशत है।

प्रमुख क्यूओएस मापदंड

सीएसएसआर : कॉल सेटअप सफलता दर (प्रतिशत में), सीएसटी : कॉल सेटअप समय (सेकंड में), डीसीआर : ड्रॉप कॉल दर (प्रतिशत में) और एमओएस

सारांश-वॉयस सेवाएँ

कॉल सेटअप सफलता दर : एयरटेल, एमटीएनएल, आरजेआईएल और वीआईएल की ऑटो-सिलेक्शन मोड (5 जी/4 जी/3 जी/2 जी) में कॉल सेटअप सफलता दर क्रमशः 99.50 प्रतिशत , 86.53 प्रतिशत , 99.30 प्रतिशत और 98.59 प्रतिशत है।

कॉल सेटअप समय : एयरटेल, एमटीएनएल, आरजेआईएल और वीआईएल में ऑटो-सिलेक्शन मोड (5 जी/4 जी/3 जी/2 जी) में कॉल सेटअप समय क्रमशः 0.82, 3.62, 0.66 और 0.69 सेकंड है।

ड्रॉप कॉल दर : एयरटेल, एमटीएनएल, आरजेआईएल और वीआईएल में ऑटो-सिलेक्शन मोड (5 जी/4 जी/3 जी/2 जी) में ड्रॉप कॉल दर क्रमशः 0.00 प्रतिशत , 7.46 प्रतिशत , 0.00 प्रतिशत और 0.20 प्रतिशत है।

कॉल साइलेंस/म्यूट दर : पैकेट स्विच्ड नेटवर्क (4 जी/5 जी) में एयरटेल, आरजेआईएल और वीआईएल की साइलेंस कॉल दर क्रमशः 0.76 प्रतिशत , 2.53 प्रतिशत और 0.88 प्रतिशत है।

मीन ओपीनियन स्कोर (एमओएस) : एयरटेल, एमटीएनएल, आरजेआईएल और वीआईएल का औसत एमओएस क्रमशः 4.00, 2.73, 3.80 और 4.38 है।

भारत-यूएई ने तीसरी सीईपीए संयुक्त समिति की बैठक बुलाई; द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के पार

(जीएनएस)।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने नई दिल्ली में भारत-यूएई सीईपीए (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता) के अंतर्गत संयुक्त समिति की तीसरी बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की। बैठक की सह-अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री अजय भादू और यूएई के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्य सहायक अवर सचिव जुमा अल कैत ने की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार में हुई तीव्र वृद्धि का स्वागत किया, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 100.06 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। यह 19.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दशार्ता है और भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से एक के रूप में यूएई की स्थिति की पुष्टि करता है। भारत-यूएई संयुक्त आयोग द्विपक्षीय व्यापार में प्रगति की समीक्षा, चुनौतियों का समाधान और सीईपीए को लागू करने के लिए प्राथमिक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है।

दोनों पक्षों ने सीईपीए के अंतर्गत प्रगति की व्यापक समीक्षा की। इसके साथ ही बाजार पहुंच के मुद्दों, डेटा साझाकरण, गोल्ड टीआरक्यू के आवंटन, एंटी-डंपिंग मामलों, सेवाओं, उत्पत्ति के नियमों, बीआईएस लाइसेंसिंग आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। भारतीय पक्ष ने पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से गोल्ड टीआरक्यू आवंटित करने के अपने हालिया निर्णय के बारे में भी यूएई को जानकारी दी।

दोनों पक्षों ने हाल ही में हुई उच्च-स्तरीय बैठकों की समीक्षा की, जिनमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल जायौदी के बीच मुंबई और दुबई में हुई बैठकें शामिल हैं। उन्होंने वर्ष 2030 तक गैर-तेल/गैर-कीमती धातु व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की ओर अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। चचार्ओं में फार्मास्यूटिकल्स में नियामक सहयोग, उत्पत्ति प्रमाणपत्रों (वह आधिकारिक दस्तावेज, जो यह प्रमाणित करता है कि किसी उत्पाद का निर्माण किस देश में हुआ है) से संबंधित मुद्दों का समाधान, बीआईएस समन्वय तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), भारत और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एमओसीसीएई), संयुक्त अरब अमीरात के बीच खाद्य सुरक्षा एवं तकनीकी आवश्यकताओं पर समझौता ज्ञापन पर शीघ्र हस्ताक्षर शामिल थे।

बैठक का समापन दोनों पक्षों के बीच व्यापार सुगमता, नियामक सहयोग, डेटा साझाकरण को मजबूत करने और सेवा उपसमिति की बैठक आयोजित करने पर सहमति के साथ हुआ। यूएई प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल के साथ भी बैठक की, जहां दोनों पक्षों ने सीईपीए के अधिकतम उपयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। यूएई प्रतिनिधिमंडल की यह यात्रा व्यापार संतुलन को मजबूत करने, बाजार के अवसरों का विस्तार करने और सीईपीए के तहत रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दशार्ती है।

दूरसंचार विभाग द्वारा दूरसंचार साइबर सुरक्षा (टीसीएस) नियम, 2025 में संशोधन

- साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, टेलीकॉम पहचान सुरक्षा बढ़ाने और डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा की दिशा में एक कदम

दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया है कि टीसीएस नियम 2024 में किए गए संशोधन लागू हैं और इन्हें लागू किया जा सकता है।

(जीएनएस)।

दूरसंचार विभाग ने 22.10.2025 को दूरसंचार साइबर सुरक्षा (टीसीएस) नियम, 2024 में संशोधन किया है। यह संशोधन उन महत्वपूर्ण कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जो बैंकिंग, ई-कॉमर्स और शासन जैसे क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के साथ टेलीकॉम पहचानों के तेजी से एकीकरण के कारण सामने आई हैं। यह संशोधन सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार दूरसंचार संचालन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

संशोधित नियमों का उद्देश्य मौजूदा नियामकीय कमियों को दूर करना और टेलीकॉम पहचानों का उपयोग करने वाली संस्थाओं के

साथ सहयोगी तंत्र के माध्यम से साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। इन नियमों में कई नए ढाँचे शामिल किए गए हैं, जो लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करते हैं।

मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्मः वित्तीय और डिजिटल सेवाओं से मोबाइल नंबरों की बिना पुष्टि वाली लिंकिंग के कारण बढ़ रहे म्यूल अकाउंट्स और पहचान धोखाधड़ी (आईडेंटिटी फ्रॉड) को रोकने के लिए नियमों में एमएनवी प्लेटफॉर्म को औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। यह प्रणाली सेवा प्रदाताओं को एक विकेंद्रीकृत और गोपनीयता-सुरक्षित प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह सत्यापित करने में सक्षम बनाती है कि किसी सेवा में उपयोग किया जा रहा मोबाइल नंबर वास्तव में उसी व्यक्ति का है, जिसकी जानकारी उनके रिकॉर्ड में मौजूद है। इससे डिजिटल लेन-देन में भरोसा और सुरक्षा दोनों बढ़ती है।

रीसेल डिवाइस स्क्रबिंगः भारत का तेजी से बढ़ता सेकंड-हैंड डिवाइस बाजार ब्लैकलिस्टेड, चोरी किए हुए या क्लोन किए गए फोन के प्रसार का केंद्र बनता जा रहा है, जिससे असली खरीदार कानूनी परेशानी में पड़ सकते हैं। संशोधित नियमों के तहत अब रीसेल या रिफर्बिश्ड डिवाइस बेचने वाले सभी संस्थानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे हर डिवाइस के क्टएक नंबर को रीसेल से पहले ब्लैकलिस्टेड आईएमइआई के केंद्रीकृत डेटाबेस में जांचें (स्क्रब करें)। यह उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चोरी हुए उपकरणों का पता लगाने में मदद करता है।

टेलीकॉम आइडेंटिफायर यूजर एंटिटी की ज़िम्मेदारियाः यह मानते हुए कि अब कई सेक्टर ऑथेंटिकेशन और सर्विस डिलीवरी के लिए टेलीकॉम आइडेंटिफायर (जैसे मोबाइल नंबर, आईएमइआई और आईपी) का इस्तेमाल करते हैं, नियम 'ळक्वए' को डिफाइन करते हैं और उन्हें खास, रेगुलेटेड हालात में सरकार के साथ जरूरी टेलीकॉम-आइडेंटिफायर डेटा शेयर करने के लिए जरूरी बनाते हैं। इससे टेलीकॉम से जुड़े साइबर फ्रॉड से निपटने में बेहतर ट्रेसेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन पक्का होता है, साथ ही डेटा प्रोटेक्शन नॉर्म्स का पालन भी बना रहता है।

कुल मिलाकर, इन बदलावों का मकसद टेलीकॉम से होने वाले फ्रॉड से भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को सुरक्षित रखना, डिवाइस ट्रेसेबिलिटी को मजबूत करना और टेलीकॉम आइडेंटिफायर का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल पक्का करना है। टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स, 2025 एक मजबूत, इंटरऑपरेबल और भविष्य के लिए तैयार टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की ओर एक अहम कदम है जो इनोवेशन, प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच बैलेंस बनाता है।

टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स, 2025 को भारत के गजट में नोटिफिकेशन जी एस आर 771(ई) तारीख 22.10.2025 के जरिए अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, एक अनजाने में हुई गलती की वजह से, जबकि कंसल्टेशन के लिए एक और रूल पब्लिश करने का इरादा था, टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स, 2025 को भारत के गजट में नोटिफिकेशन जी एस आर 796(ई) तारीख 29.10.2025 के जरिए दोबारा पब्लिश कर दिया गया। यह गलती अब टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जी एस आर 863(ई) तारीख 25.11.2025 के जरिए ठीक कर दी है, जो टीसीएस अमेंडमेंट रूल्स के अनजाने में दोबारा पब्लिश होने को रद्द करता है और यह रद्द होना किसी भी तरह से टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी रूल में ओरिजिनल अमेंडमेंट को इनवैलिड नहीं करता है, जिसने इसे पहली बार लागू किया था।

सरकार यह साफ करती है और दोहराती है कि टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स, 2025, जिन्हें शुरू में जी एस आर 771(ई) के तहत 22.10.2025 को नोटिफाई किया गया था, अभी भी लागू हैं और लागू किए जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री 28 नवंबर को कर्नाटक और गोवा जाएंगे

प्रधानमंत्री उडुपी में श्री कृष्ण मठ का दौरा करेंगे और लक्ष कंठ गीता पारायण में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री कृष्ण गर्भगृह के सामने स्थित सुवर्ण तीर्थ मंडप का शुभारंभ करेंगे और पवित्र कनकना किंडी के लिए कनक कवच समर्पित करेंगे

प्रधानमंत्री गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष समारोह में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री प्रभु श्री राम की 77 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 28 नवंबर को कर्नाटक और गोवा का दौरा करेंगे। सुबह लगभग 11:30 बजे प्रधानमंत्री कर्नाटक के उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ के दर्शन करेंगे। इसके बाद, वे गोवा जाएंगे, जहां दोपहर लगभग 3:15 बजे वे श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 'सार्ध पंचशतामनोत्सव' में भाग लेंगे।

उडुपी में प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री उडुपी में श्री कृष्ण मठ का दौरा करेंगे और लक्ष कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें छात्रों, भिक्षुओं, विद्वानों और विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों सहित एक लाख प्रतिभागी भाग लेंगे, जो एक स्वर में श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करेंगे।

प्रधानमंत्री कृष्ण गर्भगृह के सामने स्थित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे और पवित्र कनकना किंदी के लिए कनक कवच (स्वर्ण कवच) समर्पित करेंगे। कनकना किंदी एक पवित्र द्वार है। ऐसा माना जाता है कि संत कनकदास ने इसी द्वार से भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन किए थे। उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ की स्थापना 800 वर्ष पूर्व वेदांत के द्वैत दर्शन के संस्थापक श्री माधवाचार्य ने की थी।

गोवा में प्रधानमंत्री

श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष के उत्सव 'सार्ध पंचशतामनोत्सव' के अवसर पर प्रधानमंत्री दक्षिण गोवा के कैनाकोना स्थित मठ के दर्शन करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे और मठ द्वारा विकसित 'रामायण थीम पार्क गार्डन' का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे।

श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ, पहला गौड़ सारस्वत ब्राह्मण वैष्णव मठ है। यह द्वैत संप्रदाय का अनुसरण करता है, जिसकी स्थापना जगद्गुरु माधवाचार्य ने 13वीं शताब्दी में की थी। इस मठ का मुख्यालय कुशावती नदी के तट पर, दक्षिण गोवा के एक छोटे से कस्बे पर्तगाली में स्थित है।

एनबीए ने एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क के तहत महाराष्ट्र को 5.34 करोड़ रुपए जारी किए

(जीएनएस)।

स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और निष्पक्ष एवं न्यायसंगत लाभ-बंटवारे को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदमों की श्रृंखला में, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने लगभग 85 जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) को 5.34 करोड़ रु जारी किए हैं। ये बीएमसी महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा तहसील और बृहन्मुंबई नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न नगर और ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आती हैं। यह धनराशि महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से वितरित की जाएगी।

यह विज्ञप्ति एक ऐसे मामले के बाद जारी की गई है जिसमें एक कंपनी ने मिट्टी के सूक्ष्मजीवों – बैसिलस प्रजाति के जीवाणुओं का उपयोग प्रोबायोटिक उत्पाद विकसित करने के लिए किया। उल्लेखनीय है कि लगभग 15% एबीएस अनुप्रयोग सूक्ष्मजीवों तक पहुँच के लिए हैं, जो एक महत्वपूर्ण तथ्य को रेखांकित

करता है – ' सूक्ष्म ' जीव किसानों, स्थानीय समुदायों, बीएमसी और अन्य हितधारकों के लिए ' वृहद ' लाभ उत्पन्न कर सकते हैं ।

यह पहल एनबीए की इस प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है कि स्थानीय समुदाय, जो जैव विविधता के सच्चे संरक्षक हैं, को मान्यता और उचित एवं न्यायसंगत लाभ प्राप्त हों। ऐसा करके, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत के सतत और समावेशी जैव विविधता प्रबंधन का समर्थनकरता है, जहाँ संरक्षण के प्रयास समुदाय की समृद्धि और कल्याण में प्रत्यक्ष योगदान देते हैं।

इससे पहले, एनबीए ने महाराष्ट्र में 108 बीएमसी और 7 संस्थानों को 2.56 करोड़ रु से अधिक की राशि जारी की थी। 5.34 करोड़ रु का वर्तमान संवितरण इस प्रगति में उल्लेखनीय योगदान देता है। इस राशि के जारी होने के साथ, भारत का कुल एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग संवितरण 116 करोड़ रु की राशि को पार कर गया है। भारत एबीएस तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन के मामले में दुनिया में अग्रणी है।